भारत के वित्तीय संस्थानों में पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता

CFA
Centre for Financial Accountability

भारत के वित्तीय संस्थानों में पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता

CFA
Centre for Financial Accountability

लेखक: **अमीतांशु वर्मा, प्रिया दर्शनी**
हिंदी अनुवाद : विवेक कुमार सेन
आवरण एवं डिज़ाइन : **हरिप्रिया हर्षण**

प्रकाशक: **सेंटर फॉर फाइनेंसियल अकाउंटिबिलिटी**
आर 21, साउथ एक्सटेंशन पार्ट II
नयी दिल्ली – 110049

वैबसाइट : www.cenfa.org ईमेल: info@cenfa.org

नवंबर 2023

सर्वाधिकार मुक्त: इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से का उपयोग गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि संदर्भ का उल्लेख किया जाएगा तो हमें खुशी होगी।

केवल निजी वितरण के लिए।

CFA
Centre for Financial Accountability

विषय सूची

1. भूमिका..... 1
2. पर्यावरण, सामाजिक जवाबदेही नीति और भारत..... 9
3. विभिन्न दृष्टिकोणों से जवाबदेही नीति अपनाने की आवश्यकता..... 15
4. भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन तंत्र..... 19
5. निष्कर्ष..... 21
6. संदर्भ सूची..... 24

बॉक्स

1. पवागड़ा सोलर पार्क.....3
2. मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल.....5
3. रक्षोपाय नीतियां क्या हैं?.....6
4. तीस्ता जल विद्युत परियोजना.....8
5. रक्षोपाय नीतियों के उत्पत्ति और विकासक्रम 10
6. सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट.....12

भूमिका

ज़्यादातर देशों द्वारा बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्य माना जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में भी अधिक मान्य है। वास्तव में वृहद आधारभूत संरचनाएं और विकास परियोजनाएं औपनिवेशिक काल से ही विकास के प्रतिमान का द्योतक रही हैं। बड़े बांध, कोयला एवं अन्य खनिजों की बड़ी खनन परियोजनाओं और भारी उद्योगों ने देश के कथित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1990 के बाद हमारे देश में विकास की अवधारणा में, जनता को लाभ पहुंचाने वाले सामाजिक बुनियादी ढाँचे के बजाय वृहद संरचनाओं की ओर एक तीव्र झुकाव आसानी से देखा जा सकता है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों के इलाकों और प्राकृतिक संसाधनों के बीच परस्पर जुड़ाव बनाते हुए विभिन्न विशालकाय आधारभूत संरचनाओं का निर्माण तथा ऊर्जा सहित अन्य परियोजनाओं का विस्तार, तेजी से जारी है। आर्थिक विकास के विमर्श में इन परियोजनाओं के योगदान को आँका तो जाता रहा है लेकिन परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदाय, जिनका जीवन और आजीविका परियोजना स्थल के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुयी है, पर पड़ने वाले प्रभावों की लगातार अनदेखी की जाती रही है।

जहां एक ओर विकास परियोजनाओं की संख्या में इजाफ़ा हुआ है वहीं इन परियोजनाओं के दुष्प्रभावों के खिलाफ़ लामबंदी भी हुई है। 1920 में टाटा द्वारा मुलशी पेठा में बनाये जा रहे एक बांध के निर्माण के दौरान जबरिया विस्थापन के खिलाफ़ पुणे में 11,000 से अधिक लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया था जो केवल एक शुरुआत थी। 1930 में पहले कंक्रीट बांध के निर्माण के बाद देश में प्रमुख बांधों की संख्या 1950 तक बढ़कर 100 तथा 1985 तक 1000 से अधिक हो गई थी। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, भारत में 2022 तक 5,265 बड़े बांध बन चुके हैं तथा 437 निर्माणाधीन हैं। इस संदर्भ में सीडब्ल्यूसी द्वारा 54 बड़े बांधों के महत्वपूर्ण अध्ययन से पता चलता है कि एक बड़े बांध से विस्थापित होने वाले लोगों की औसत संख्या 44,182 होती है। देश में बांधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन उनसे बड़े पैमाने पर हो रहे विस्थापन और अन्य मुद्दों को हल करने के तंत्र विकसित नहीं किए गए हैं। डाउन टू अर्थ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नियोजित विकास के पहले तीन दशकों के भीतर विस्थापित लोगों में से केवल पच्चीस प्रतिशत लोगों का ही पुनर्वास किया गया है। भाखड़ा-नंगल परियोजना (1960) के दौरान ऊना और बिलासपुर जिलों में विस्थापित हुए 2108 परिवारों में से अब तक केवल 750 परिवारों का ही पुनर्वास किया गया है। अन्य परियोजनाओं की कहानी भी समान ही है। सरदार सरोवर परियोजना एक व्यापक रूप से जानी जाने वाली परियोजना है। इसमें 3,000 छोटे, 135 मध्यम और 30 बड़े बांध एवं नहर परियोजनाएं शामिल हैं जो 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा घाटी में बनाए जाने के लिए योजनाबद्ध हैं। प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा परिकल्पित इस बांध के निर्माण का कार्य 1980 के दशक में शुरू हुआ। सरदार सरोवर बांध, उन सभी नियोजित बांधों में सबसे बड़ा बांध है जिसका लोकार्पण प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में किया गया था। बांध का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पिछले तीन दशकों से नर्मदा घाटी के लोगों ने विस्थापन के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है। इतने लंबे संघर्ष के बावजूद घाटी में करीब 200 गांव डूब के कगार पर अभी भी खड़े हैं। हजारों लोग अब भी मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।

द्रुत गति से बढ़ रही कथित विकास परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन का समाधान निकालने के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। तेज़ी से बढ़ते विस्थापन की सबसे अधिक मार देश के आदिवासी समुदाय पर पड़ रही हैं। 2016 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गयी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 1950 से 1990 के बीच देश में 87 लाख आदिवासी विस्थापित हुए थे जो कुल विस्थापितों का 40 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे आदिवासी बहुल राज्य, भारत के कोयला भंडार का 70 प्रतिशत, उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का 80 प्रतिशत, बॉक्साइट का 60 प्रतिशत और क्रोमाइट भंडार का लगभग लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, इसलिए ये खनिज दोहन एवं खनन परियोजनाओं का केंद्र बन गए हैं। साफ जाहिर है कि यदि विकास के प्रतिमान का सही तरीके से आकलन नहीं किया गया तो इसकी मानवीय क्षति भयावह हो सकती है। आंतरिक विस्थापितों की निगरानी रखने वाले केंद्र (आईडीएमसी, 2007) के अनुसार, कथित विकास प्रेरित परियोजनाओं के चलते 21.3 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ है जिसमें बांधों से 16.4 मिलियन, खानों से 2.55 मिलियन, औद्योगिक विकास से 1.25 मिलियन और वन्यजीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों से 0.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं।

विस्थापन, त्रासदी के विभिन्न पहलुओं में से एक है। परियोजनाओं का पर्यावरण और पारिस्थितिकीय तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव चिंता का एक और गंभीर विषय है जिसे अब तक उस गंभीरता से नहीं लिया गया है जितना यह महत्वपूर्ण था। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (2020) के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए देशों में 5वें स्थान पर हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करते हुए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी, 2021) कहना है कि भारत में जलवायु संकट के अधिकांश प्रभाव अपरिवर्तनीय हैं, जिन्हें ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कमी लाने की बावजूद सुधारा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत के वित्तीय संस्थान पिछले वर्षों की तरह, छह देशों में से तीसरे सबसे बड़े निवेशक थे जो दुनिया के कोयला निवेश का 80 प्रतिशत वित्तपोषण करते थे। सागरमाला, समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़लने के लिए एक बंदरगाह आधारित विकासात्मक परियोजना है, जिसमें 6.01 लाख करोड़ रूपये की लागत वाली 574 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में 121 पूरी हो चुकी हैं तथा 201 विकास के चरण में हैं। इसमें अब तक कुल 7,78,080 करोड़ के निवेश में से 1 प्रतिशत से भी कम राशि सामुदायिक विकास के लिए खर्च की गई है। पारिस्थितिकीय तंत्र को होने वाले संभावित नुकसान की रोकथाम अथवा उसकी तैयारी के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। भारतीय तट घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां मछुवारा समुदायों के 40 लाख लोगों की अनुमानित आबादी हैं। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने चक्रवात, तूफान, ज्वार-भाटे की आवृत्ति में वृद्धि की है। क्षेत्र में इन घटनाओं की बारंबारता, बड़े पैमाने पर तटीय कटाव सहित अन्य पर्यावरणीय प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहे है। केरल में शनगुमुघम और कोवलम समुद्र तट के अनियमित तटीय कटाव इसी प्रकार के उदाहरण हैं जो विझिंजम समुद्री बंदरगाह के ठूठने के कारण हो सकते हैं।

मौजूदा विकास की अवधारणा में, विभिन्न परियोजनाएँ अलग-थलग ना होकर व्यापक रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 2000 के दशक में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की शुरूआत हुयी थी जिसमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हुआ है। गहराई से पड़ताल करने पर ज्ञात होता है कि ये सभी विशेष आर्थिक क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। आज विकास का मॉडल एक इंटरलॉक सिस्टम बन गया है जो एक दूसरे से गूँथा हुआ है। इसलिए अब यह परियोजनाएं नहीं, बल्कि परियोजनाओं का एक समूह है जैसे - स्मार्ट सिटी, सागरमाला, भारतमाला, औद्योगिक गलियारे, सड़क और रेल गलियारे, सौर ऊर्जा पार्क, थर्मल पावर क्लस्टर आदि। विशालकाय परियोजनाओं के ये समूह, पारिस्थितिकी और सामाजिक क्षति के साथ-साथ भारी वित्तीय लागत का आधार बन गए हैं।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अभी अकेले कुल 7,400 परियोजनाएँ हैं। जिनमें से 2020 तक 1.10 लाख करोड़ रूपए (US$ 15.09 बिलियन) लागत वाली 217 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी है। इसी तरह गति शक्ति मास्टर प्लान में 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, 100 कार्गो टर्मिनल, 11 औद्योगिक गलियारे, रक्षा उत्पादन में 1.7 लाख करोड़ रूपये का कारोबार, 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर और 109 फार्मास्युटिकल क्लस्टर के अनुबंध शामिल हैं। इसके तहत राज्यों को 1 लाख करोड़ रूपये का आवंटन भी किया जाना है। सिर्फ इस योजना के भीतर ही 5590 किलोमीटर सड़क, 17000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बनाया जाना है।

गति शक्ति योजना अपने आप में एक विशाल मिशन की तरह है। जबकि यह विभिन्न गति शक्ति योजना एक विशाल मिशन की तरह लग सकती है, लेकिन यह कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। इसके अलावा कम से कम 20 अन्य मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनमें बुलेट ट्रेन, हाइपर लूप प्रोजेक्ट, कम से कम 25 शहरों में मेट्रो रेल, कल्पसर बांध परियोजना, गुड्स एंड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भारतमाला परियोजना (इसके तहत देश के 550 जिलों को आपस में जोड़ने वाला 26000 किमी का आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाना है जिसकी अनुमानित लागत 6,92,324 करोड़ रूपये है), कम से कम सात अल्ट्रा-मेगा बिजली परियोजनाएं (प्रत्येक की अनुमानित लागत 15000 करोड़) का लक्ष्य है। 25 सोलर पार्क (अल्ट्रा-मेगा सौर परियोजना) जिन्हे 2017 में बढ़ाकर 50 कर दिया गया था को बनाया जाना लक्षित है जिसमें कई सोलर पार्कों का काम पूरा हो चुका हैं कुछ अभी भी निर्माणाधीन हैं। यहाँ मुख्य सवाल यह उठता है कि इन विशालकाय परियोजनाओं का वित्तपोषण आखिरकार कौन कर रहा है?

पवागड़ा सोलर पार्क

स्थान : **तुमकुर, कर्नाठक**

क्षमता : **2000 मेगावाट**

क्षेत्र : **नवीकरणीय सोलर ऊर्जा**

वित्तपोषण करने वाले संस्थान:

- राष्ट्रीय वित्त संस्थान: कोठक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान: रैबोबैंक, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, बीएनपी, परिबास, डीबीएस बैंक, मिज़ुहो कॉर्पोरेट बैंक, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन।

सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:

- चरवाहों के पास अपने पशुओं के लिए इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं बचा है।
- परिवार के बच्चों और वृद्धों को छोडकर काम की तलाश में बाहर (प्रवास) में निकलन पड़ा।
- पांच गांवों में फैली कुल 13,000 एकड़ जमीन की वनस्पति नष्ट कर दी गयी, चारों और बाड़ लगाकर जमीन को समतल कर दिया गया।
- बाड़ लगाने और समतलीकरण की प्रक्रिया ने अधिकांश जल संग्रहण, संचयन और निकासी के पुराने ढांचों को तोड़ दिया जिसे अतीत में सोच समझकर बनाया गया था। जैसे छोटे बांध, जलसंग्रहण के लिए आने वाली पानी की धाराएँ (राजकालुवे), पानी के भंडारण के लिए ढीलें बोल्डरों से बनाई गयी संरचनाएं (कुआं, बाबड़ी), आदि को तहस नहस कर दिया गया।
- सोलर पैनलों पर धूल मिट्टी ना जमें इसलिए इसे लगातार धोना पड़ता है। पैनलों की सफाई के लिए भारी मात्रा में पानी जमीन के खुदाई करके सर्ज़ प्रोटेक्शन डिवाइस (एसपीडी) के माध्यम से निकाला जाता है जो उच्च टीडीएस (ठोठल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स) पानी होता है। इसे साफ करने में भी काफी ऊर्जा खर्च होती है।

सामग्री स्त्रोत: Cenfa.org

डेठा स्त्रोत: वाणिज्यिक ऑनलाइन डेठाबेस, वार्षिक रिपोर्ट

Image Source: **https://edition.cnn.com/2019/04/24/middleeast/gallery/global-solar-megaprojects/**

भारतीय वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंक अब ऐसी विशालकाय परियोजनाओं के प्राथमिक ऋणदाताओं में से एक बन गए हैं। 2000 के दशक से ही वाणिज्यिक बैंकों ने अपने कारोबार को विस्तार करते हुये, छोटे पैमाने पर जमा और ऋण देने की सीमाओं से परे जाकर इन विशालकाय विकास परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर उधार देने की शुरूआत कर दी थी। सेंटर फॉर फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी (सीएफ़ए) ने 2022 की अपनी "कोल ट्रेल" नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया है कि 2005 से 2022 के बीच 1000 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाली परियोजनाओं की कुल संख्या 140 थी, जो या तो उत्पादन कर रही थी अथवा उन्हे सुरक्षित पर्यावरण मंजूरी हासिल या विचारार्थ थी। इन 140 परियोजनाओं में से 132 प्लांटों के विशेष ऋणदाताओं की जानकारी हासिल की जा सकी। इन परियोजनाओं की कुल ऋण राशि ₹ 76,21,087.9 मिलियन थी जिसमें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों का 93% हिस्सा था जो ₹ 71,17,418.9 मिलियन के बराबर है। इन राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में वाणिज्यिक बैंक भी शामिल हैं जो सार्वजनिक धन पर चलते हैं। ऑयलचेंज इंटरनेशनल ने 2021 में 'हाउ सेंट्रल बैंक आर फंडिंग क्लाइमेट क्राइसिस' पर अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय बैंक विश्व स्तर पर कोयला आधारित परियोजनाओं के चौथे सबसे बड़े वित्तपोषक है। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक ने जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के वित्तपोषण में 21.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। बचत, जमा और निवेश के माध्यम से उगाहा गया यह भारतीय जनता का पैसा है जिसे बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली और खनन परियोजनाओं में लगाया जा रहा है।

इतने बड़े पैमाने पर दिये जा रहे ऋणों का असर स्वयं वित्तीय संस्थानों पर भी पड़ता है। 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर) के बाद से, भारतीय बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर दिए गए ऋण से अपनी गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) को कम करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। तमाम कोशिशों के बावजूद सात वर्षों के बाद भारतीय बैंकों को अपना एनपीए कम करने के लिए एकमात्र तरीका राइट ऑफ (दिये गए ऋण को बट्टे खाते मे डालना) करना पड़ा है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में, आरबीआई ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में अकेले भारतीय बैंकों ने अपने एनपीए को कम करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले है। इस दौरान मार्च 2022 तक, उन्होंने 1.32 लाख करोड़ रुपए वसूले जो कुल एनपीए का महज 13 प्रतिशत था। बैंक यूनियनों की रिपोर्टों के अनुसार, विलफुल डिफॉल्टर्स (जानबूझकर ऋण ना चुकाने वाले) की संख्या 2014-15 में 5349 थी, जो 2018-19 में बढ़कर 8582 हो गई थी। बट्टे खाते में डालने के अलावा, बैंकों ने एनपीए की समस्या का उपचार करने के अन्य तरीके हेयरकट (दिये गए विशेष ऋण से कम राशि स्वीकार करना) के माध्यम से भी पैसा खो दिया जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा हासिल किया जा सकता था। रिपोर्टों के अनुसार दिवालियापन संहिता पेश किए जाने के पांच साल बाद 2021 तक केवल 11 मामलों का ही निराकरण किया जा सका है जिसमें उधारदाताओं को 90 प्रतिशत तक हेयरकट देना पड़ा है। इस प्रकार देखा जाए तो दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को एक मामले का समाधान निकालने में औसतन 12 से 36 महीने का समय लगता है। फिलहाल ऋण वापसी से संबन्धित इस प्रकार के 12,438 मामले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास लंबित है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अकेले दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत लंबित मामलों को हल करने के लिए एनसीएलटी को अगले छह साल से अधिक का समय लगेगा।

जब बड़ी परियोजनाओं का काम पूरा होने में यदि अधिक समय लग रहा हो तब यह आंकड़े और अधिक चिंताजनक हो जाते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट अनुसार 150 करोड़ अथवा उससे अधिक लागत वाली कुल 1,529 परियोजनाओं में से 384 परियोजनाओं का संचालन लागत, मूल लागत से अधिक था तथा 662 परियोजनाओं को पूरा होने में देरी हुई। "1529 परियोजनाओं को पूरा करने की मूल लागत 21,25,851.67 करोड़ रुपये आंकी गई थी अब इनके पूरा होने की कुल संभावित लागत 25,78,197.18 करोड़ रुपये है, जो 4,52,345.51 करोड़ रुपये (मूल लागत का 21.28%) की कुल लागत वृद्धि को दर्शाता है। इसके आगे रिपोर्ट कहती है कि इन परियोजनाओं पर सितंबर 2022 तक 13,78,142.29 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं जो परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 53.45 प्रतिशत था। जो भी हो यदि देरी की गणना नए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर की जाए तो देरी से पूरी होने वाली परियोजनाओं की संख्या घटकर 531 हो जाती है। तब भी 603 परियोजनाओं के लिए, ना तो चालू होने का वर्ष और न ही संभावित निर्माण अवधि बताई जा रही है। 662 विलंबित परियोजनाओं में से, 133 परियोजनाओं को 1 से 12 महीने, 124 को 13 से 24 महीने, 276 परियोजनाओं में 25 से 60 महीने और 129 परियोजनाओं में 61 महीने और उससे अधिक की देरी हुई है। इन 662 विलंबित परियोजनाओं में औसतन देरी की समय सीमा 42.08 महीने है। विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनी निर्दिष्ट रिपोर्ट में समय की अधिकता के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी, वन और पर्यावरण मंजूरी हासिल करने में देरी, और बुनियादी ढांचे के सहयोग एवं संपर्क की कमी का उल्लेख किया गया है।"

मुंद्रा पोर्ट टर्मिनल

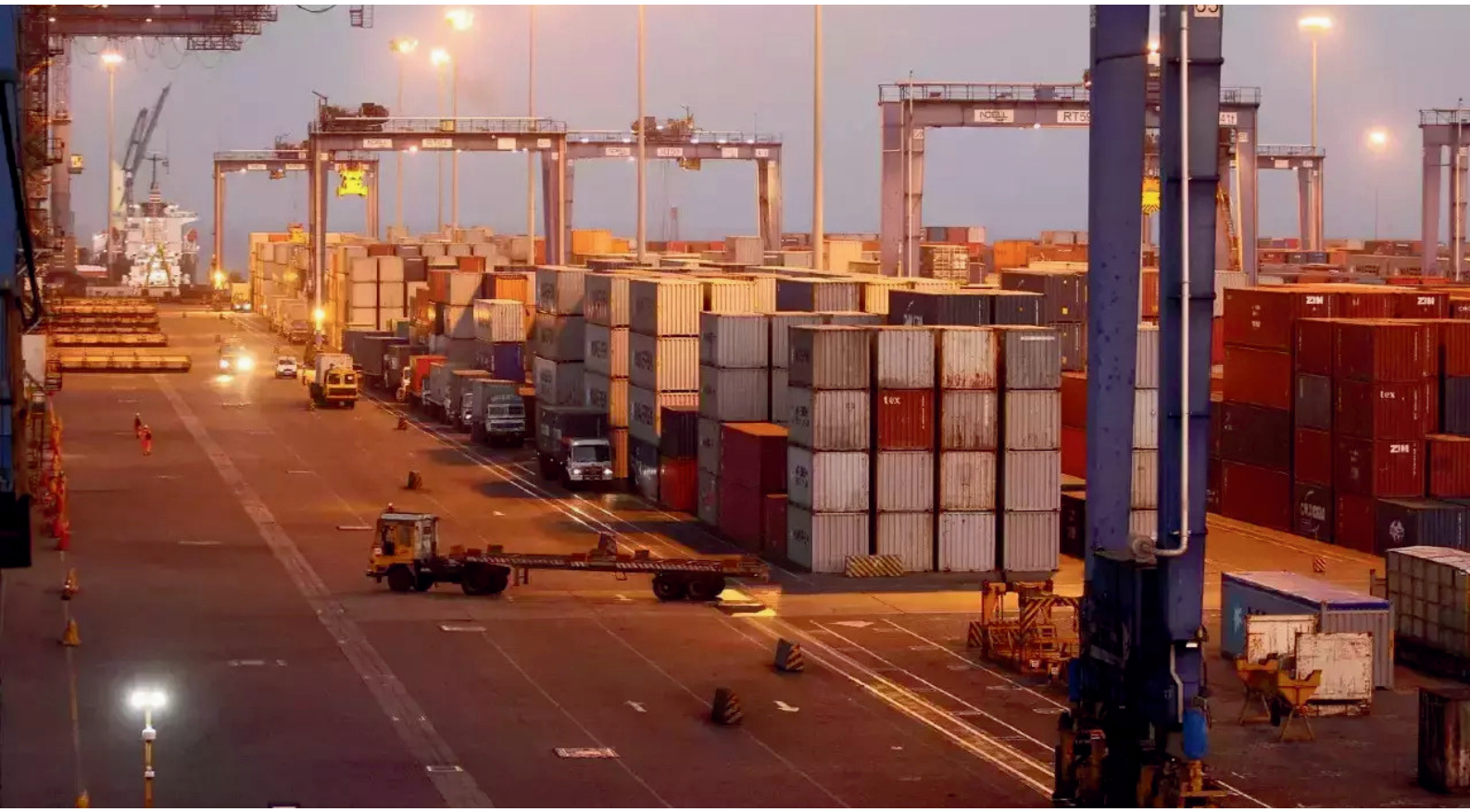

स्थान: **गुजरात**
सेक्टर: **बंदरगाह**
क्षमता:
वित्तीय संस्थान: भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक।

सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव:
मैंग्रोव का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है; बोचा द्वीप में 75 हेक्टेयर मैंग्रोव नष्ट हो गए हैं, जिसे पर्यावरण मंजूरी शर्तों के तहत संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया था।

कंपनी ने निर्माण गतिविधियों के कारण खाड़ियों के अवरुद्ध होने से बचाव के लिए सावधानी नहीं बरती है; सैटेलाइट इमेजरी में प्रस्तावित नॉर्थ पोर्ट के पास खाड़ियों के खराब होने और नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह परियोजना मछुआरों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करती है।

स्रोतः **सुनीता नारायण समिति रिपोर्ट**
स्रोत छवि: **इंडियन एक्सप्रेस में पीटीआई फोटो**
स्रोत: **वाणिज्यिक ऑनलाइन डेटाबेस**

Image Source: PTI photo in Indian Express

समस्या, स्पष्ट रूप से बहुआयामी है जो सभी को सुलझाने की मांग करती है। हमें इसके सभी प्रभावों और उनमें आपस की संबद्धता को विस्तार से समझना होगा जिसका प्रयास पुस्तिका के आगे के खंडों में किया गया है। साधारण बात यह है कि बड़े पैमाने की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला वर्तमान विकास का मॉडल किसी भी प्रकार से टिकाऊ नहीं है। यह पारिस्थितिकीय तंत्र, पर्यावरणीय, सामाजिक या वित्तीय रूप से अस्थिर है।

हालांकि ऐसे कई जनआंदोलन हुए हैं जो मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो अब भी चल रहे हैं। इन आंदोलनों के बावजूद इन परियोजनाओं को फंड देने वाले वित्तीय संस्थान लंबे समय से जांच और जबाबदेही के बाहर हैं।

वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए शायद ही कोई प्रभावी तंत्र है। परियोजना को वित्त उपलब्ध कराने के लिए भारी पैमाने पर ऋण देने वाले इन वित्तीय संस्थानों पर शायद ही कोई सवाल खड़ा करता है। फिर चाहे चाहे इन वित्तीय संस्थानों के ग्राहक हो या परियोजना से प्रभावित होने वाले लोग।

यहां हम विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण से भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता को संकलित रहे हैं। आगे इस पर विस्तार से चर्चा होगी कि वित्तीय संस्थानों के लिए पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता क्यों है तथा इसकी मांग करना क्यो जरूरी है।

पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियाँ क्या हैं?

पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियां (आगे जवाबदेही नीतियां कहा जाएगा) ज्यादातर बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से जुड़ी हैं। ये पर्यावरण और सामाजिक तंत्र (ईएसएफ) नामक ढांचे के तहत बनाई जाने वाली नीतियों का एक समूह है जिन्हे ईएसएफ नीतियों के नाम से भी जाना जाता है। ये नीतियाँ बांध, सड़क, कोयला आदि से जुड़ी विकास परियोजनाओं के प्रभावों से जनता और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की पहचान करने, बचने और उन्हे कम करने के लिए बनाई जाती हैं। ईएसएफ परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया तंत्र हैं जो समुदायों के साथ परामर्श और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता हैं। परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले मूल निवासी समुदायों को जानने का अधिकार और परियोजना शुरू होने से पहले पूर्व सूचना के आधार पर सहमति इस तंत्र का एक प्रमुख सिद्धांत है।

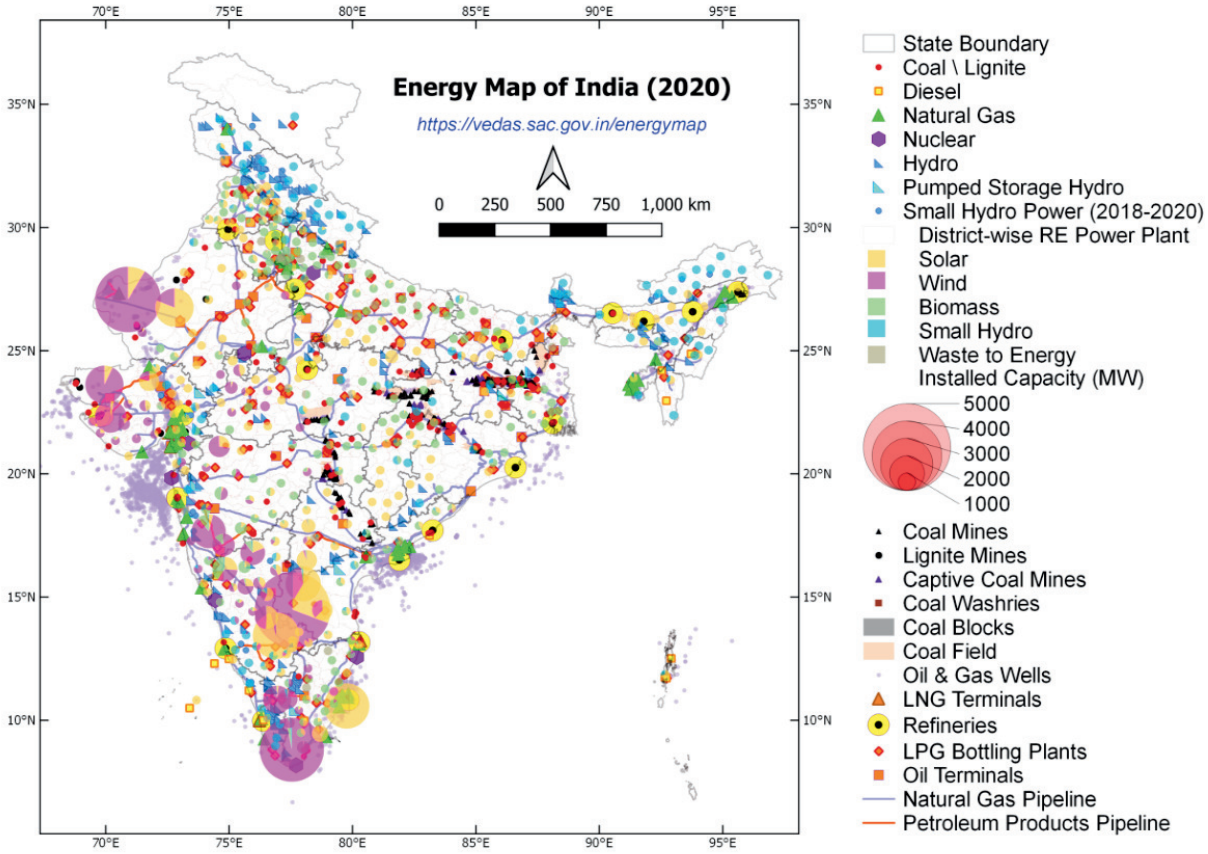

चित्र 1: भारत में ऊर्जा परियोजनाएँ

तीस्ता जलविद्युत परियोजना

स्थान: **सिक्किम**

क्षेत्र: **जल विद्युत**

वित्तीय संस्थान: **आईसीआईसीआई बैंक**

सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव

लंबे समय से, तीस्ता III परियोजना सिक्किम में सबसे विनाशकारी और अस्थिर परियोजनाओं में से एक रही है। अपनी भूमि पर लेप्चा लोगों के अधिकारों की गैर-मान्यता और उनकी पवित्र तीस्ता नदी पर बांधों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका बहिष्कार प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। लेप्चा लोगों का उनकी पवित्र तीस्ता नदी और उनके अंतिम रिजर्व, जोंगू के साथ संबंध पूरी तरह से अपमानित किया गया है।

परियोजना के निर्माण के लिए किए गए विस्फोट और सुरंगों की बोरिंग के कारण पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ और बांध स्थल के पास के घर नष्ट हो गए। नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी, भूकंपीय प्रभावों, ट्रांसमिशन लाइनों, कम प्रवाह के प्रभाव और लेप्चा लोगों पर विस्फोट जैसे अन्य प्रभावों पर एक समग्र प्रभाव मूल्यांकन, इसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) से अनुपस्थित है।

अगस्त 2006 में परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी मई 1999 में तीस्ता चरण V जलविद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अपनी शर्त का उल्लंघन करती है, जिसमें कहा गया था: "वहन क्षमता अध्ययन पूरा होने तक सिक्किम में किसी भी अन्य परियोजना पर पर्यावरण मंजूरी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

Content and Image Source: e-pao.net

1. पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा उपाय और भारत

व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को उनकी गतिविधियों के गैर-वित्तीय प्रभावों के लिए जवाबदेह ठहराने के प्रयास होते रहे हैं। इस तरह का प्रयास संयुक्त राष्ट्र के निवेश सिद्धांतों द्वारा 2006 में अपने हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा छह सिद्धांतों का पालन कराने का प्रयास किया गया था। 2011 में, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के लिए वित्तीय क्षेत्र एवं व्यवसायों की जबाबदेही पर ज़ोर देते हुए व्यापार और मानवाधिकारों पर अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रकाशित किया था। इसी प्रकार 2019 में उत्तरदायी बैंकिंग के सिद्धांत को लाया गया जो विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आया था कि अब बैंक अपने दिये गए उधार और किए गए निवेश के प्रभावों के प्रति गैर जिम्मेदार नहीं रह सकते हैं। हालांकि एक या दो को छोड़कर इनमें से किसी भी पहल पर, भारतीय वित्तीय संस्थानों ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पर्यावरण, समाज और प्रशासन पर ज़ोर देते हुये सन 2007 से कुछ पहल ली थी जो वित्तीय संस्थाओं की जवाबदेही तय करने वाले ठोस तंत्र को अनिवार्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 23 अप्रैल, 2021 को केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क (एनजीएफ़एस) की सदस्यता ली है ताकि वह इसका लाभ उठा सके और ग्रीन फाइनेंस के लिए हो रहे वैश्विक प्रयासों में योगदान दे सके। 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के अवसर पर, एनजीएफ़एस ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वैश्विक पहलकदमी में योगदान करने की अपनी इच्छा को दोहराया है। एनजीएफ़एस वित्तीय प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में हो रहे सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने और उसे विस्तार देने का प्रयास करेगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 नवंबर, 2021 को अपना एक वक्तव्य 'स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम - एनजीएफएस' जारी किया है।

2007 से आरबीआई ने बैंकों को 'सलाह' दी थी कि वे सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित गैर-वित्तीय मुद्दों पर ध्यान दें। बैंको के बोर्डों द्वारा अनुमोदन लेकर सतत और ठिकाऊ विकास हासिल करने के लिए उपयुक्त और उचित कार्य योजना बनाने पर विचार करें। इस संदर्भ में, परियोजना वित्त और कार्बन ट्रेडिंग पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमों (आईएफसी) के सिद्धांतों, मुख्यतः भूमध्य रेखा सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमित आधार पर अपने आप को बदलते घटनाक्रमों से अवगत रखें और इस तरह के घटनाक्रमों के आलोक में अपनी रणनीतियों/योजनाओं आदि में सामंजस्य स्थापित करें तथा परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को संशोधित करें। भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता संभालने के साथ ही आरबीआई ने इन परामर्शों को पुनः दोहराया है।

यहां तक कि जब बैंकों के ऋण देने वाले विभागों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, तब भी आरबीआई ने बैंकों के लिए अनिवार्य पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों को सुनिश्चित करने से परहेज किया है। जबकि जनता पर पड़ने वाले प्रभावों के चलते जलवायु प्रशासन और रक्षोपाय कानूनों के बीच राज्य को केंद्रीय मध्यस्थ के रूप में देखा गया है। वर्षों से वित्तीय संस्थानों पर विकसित वैश्विक समझ घरेलू क़ानूनों और संस्थाओं की आवश्यकता पर ज़ोर देती है जो मजबूत जवाबदेही नीतियों को पर्यावरण के स्तर पर लागू कर सके।

अब तक बैंको द्वारा सार्वजनिक दस्तावेज़ के रूप में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) रिपोर्ट हर साल भरा जाता है जो स्वैक्षिक है। 'स्वैच्छिक' मानदंड के तहत पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के मामलों में बीआरएसआर रिपोर्ट कबूतरबाजी करती है। सेबी द्वारा 10 मई 2021 को जारी सर्कुलर ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) के लिए प्रारूप जारी किया था। जिसमें कहा गया कि भले ही ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) रिपोर्ट 2012 से जारी की गयी है लेकिन जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के लिए विभिन्न चिंताओं को ध्यान में रखते हुये अधिक व्यापक रिपोर्टिंग प्रारूप बनाया जाना था। बीआरएस रिपोर्टिंग (अगस्त 2020) के प्रारूप पत्र पर परामर्श के अनुसार, ये चिंताएँ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय जोखिमों और बढ़ती असमानता के बारे में बढ़ती जागरूकता से संबन्धित हैं।

अक्टूबर 2017 में, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बनी समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा कि निदेशक मंडल को कम से कम वर्ष में एक बार रणनीति, बजट, बोर्ड मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) और उत्तराधिकार योजना पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए बैठक करना होगा। मौजूदा रिपोर्टिंग और दिशानिर्देश केवल नवीकरणीय ऊर्जा और 'हरित निवेश' को बढ़ाने, बैंकों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने आदि तक ध्यान केंद्रित करते है, लेकिन उनमें से कोई भी विशेष रूप से पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीति को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, जैसा कि बहुपक्षीय विकास बैंको (एमडीबी) द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ बैंकों ने ईएसजी नीतियों को अपनाया है जिसमें ऋण देते समय प्रभाव और जोखिम आकलन किया जाता हैं। हालांकि यह अपर्याप्त और इच्छाशक्ति की कमी से प्रभावित है।

जवाबदेही नीतियों को कैसे अपनाया और विकसित किया गया

जवाबदेही नीतियों की रूपरेखा नीतियों का एक विकासक्रम है जिसे 1980 के दशक की शुरूआत में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित विकास परियोजनाओं के हानिकारक प्रभावों के जवाब में अपनाया गया था जिसे बाद में ऋण उपलब्ध कराने वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्रो द्वारा अपनाया गया था। मूलतः जवाबदेही नीतियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित समुदायों के सामूहिक प्रतिरोध और नागरिक संगठनों (सीएसओ) द्वारा बनाए गए दबाव के चलते बनाया गया था। भारत में 1980 और 90 के दशक के दौरान नर्मदा बांध परियोजनाओं जिसमें 200,000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया गया, सहित अन्य विवादास्पद परियोजनाओं में अपनी भागीदारी के चलते विश्व बैंक को कड़ी सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसलिए विश्व बैंक को जनता और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की पहचान करने और उसे कम करने में मदद करने के लिए जवाबदेही नीति विकसित करनी पड़ी। जवाबदेही नीतियों के ढांचे में वर्तमान में 11 परिचालन नीतियां शामिल हैं जिनमें अस्वैच्छिक पुनर्वास, स्थानीय जनता, पर्यावरणीय कार्य योजनाएं, वन, प्राकृतिक निवास आदि शामिल हैं।

इन नीतियों का विकास अपने आप नहीं हुआ है बल्कि इन्हे लागू करवाने के लिए दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों की नीतियों और निवेश के उनके ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों को विरोध का सामना करना पड़ा है, मुख्यतः विकासशील देशों में इन्हे अधिक चुनौती दी गई थी।

1.1 नीतियों का अभाव

भारत में विकासात्मक वित्त और ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं ने कभी भी जनता या पर्यावरण के लिए इस प्रकार के किसी भी जवाबदेही नीतियों को आत्मसात नहीं किया। विकास के विनाशकारी मॉडल के खिलाफ देश में दशकों से कई संघर्ष होने के बावजूद वित्तीय संस्थानों पर जवाबदेही नीतियों को अपनाने का विशेष दबाब नहीं पड़ा है। हालाकि कि सरदार सरोवर बांध परियोजनाओं के खिलाफ हुये आंदोलन के चलते विश्व बैंक को जवाबदेही नीतियों और जवाबदेही तंत्रों का मसौदा तैयार करना पड़ा। लेकिन जिन संघर्षों ने विश्व बैंक को जवाबदेही नीतियाँ अपनाने और स्वतंत्र जवाबदेही तंत्रों को विकसित करने के लिए दबाब बनाया, वे राष्ट्रीय परिदृश्य और भारतीय वित्तीय संस्थानों में तब तक प्रतिध्वनित नहीं हुए जब तक कि हाल ही में अपने स्वयं के तंत्र और संस्थानों को बनाने के लिए वे खुद आगे नहीं आए।

भारत में 1990 के दशक के अंत में जब विकास वित्त संस्थान (डीएफ़आई) खुद को व्यवस्थित तरीके से रूपांतरित कर रहे थे तब दीर्घावधि के वित्त का बोझ वाणिज्यिक बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर स्थानांतरित हो गया। इससे पहले पीएसबी केवल छोटे पैमाने/खुदरा ऋणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे इसलिए उन्हें जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता नहीं थी लेकिन 2000 के दशक की शुरूआत में जब बैंक बड़ी परियोजनाओं को ऋण देने के शुरूआत की तब भी पर्यावरण या सामाजिक जवाबदेही नीति नहीं अपनाई गई।

जवाबदेही नीतियों को लागू ना करने के परिणाम सभी परियोजनाओं में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सरदार सरोवर बांध परियोजना के निर्माण में, जिसे शुरू में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया था के चलते तीन राज्यों के 245 गांवों में लगभग 41,000 परिवारों (लगभग 200,000 से अधिक लोगों) को विस्थापित हुए।

इसी तरह मुंद्रा, गुजरात में टाटा द्वारा संचालित बिजली परियोजना का समृद्धी जीवन, तटीय वनस्पतियों और मछुआरों की आजीविका के स्त्रोत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार की परियोजनाओं से समाज में हाशिये पर रहने वाले तबके आदिवासी, तटीय लोग, भूमिहीन किसान, छोटे किसान, दलित, मुस्लिम, महिलाएं और बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता हैं। इसके अलावा जलवायु, जैव विविधता और पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव सभी को प्रभावित करते है। विश्व बैंक, जो शुरू में इस परियोजना को वित्तपोषित कर रहा था, को अंततः अपने वित्त पोषण को वापस लेना पड़ा, जिससे संस्था के लिए आर्थिक और प्रतिष्ठा मूलक परिणाम सामने आए। इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं।

सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

स्थान: **सिंगरौली, मध्य प्रदेश**
सेक्टर: **थर्मल पावर प्लांट**
क्षमता: **3960 मेगावाट**

वित्तीय संस्थान:
राष्ट्रीय वित्त संस्थान - आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक इंडिया, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई)

अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान - बैंक ऑफ चाइना, चाइना एक्ज़िम बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्यात आयात बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मिज़ुहो, जापान

सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव
10 अप्रैल, 2020 को, सिंगरौली मध्य प्रदेश में सासन कोयला संयंत्र के लिए फ्लाई ऐश बांध टूट गया, जिससे जहरीले कचरे की बाढ़ आ गई, जो आस-पास के गांवों में फैल गई, हजारों एकड़ भूमि में बह गई और कृषि फसलों को नष्ट कर दिया और छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें शामिल हैं दो बच्चों।
ओआईजी की 2015 की रिपोर्ट में संयंत्र में 19 मौतों की पुष्टि की गई थी। EXIM को सौंपी गई निगरानी रिपोर्ट से पता चला कि इसके बाद कम से कम आठ और मौतें हुई हैं।

जुलाई 2014 में, स्थानीय समूह सृजन लोकहित समिति ने अन्य नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर यूएस एक्ज़िम बैंक के महानिरीक्षक (ओआईजी) के कार्यालय को पत्र लिखकर मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण और सामाजिक उल्लंघनों की ओर इशारा किया, जिन्होंने परियोजना को प्रभावित किया।

सामग्री स्रोत: cenfa.org
छवि स्रोत: reliancepower.co.in

1.2 प्रतिबद्धताएं और रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से लागू होने के बजाय स्वैच्छिक हैं।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि वित्तीय संस्थानों ने दिये गए ऋण से होने वाले प्रभावों के संबंध में अपनी भूमिका को शुरू से ही नकारा है। पारिस्थितिकी और मानव जीवन पर पड़ने वाले गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभावों के साक्ष्यों के बावजूद, वित्तीय संस्थानों ने ना तो अपनी इच्छा से गैर-वित्तीय जवाबदेही नीतियों को अपनाया, ना ही अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों अथवा नियामक अधिसूचनाओं को गंभीरता से लिया। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2019 के बाद से एक बदलाव अवश्य दिखाई दे रहा है।

यह कई कारकों का परिणाम है। जिसमें निश्चित ही मुख्यधारा में जलवायु संकट पर बहस का तीव्र होना एक है। दिखाई देने वाले गंभीर मौसमी घटनाओं ने दुनिया को, जलवायु संकट को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया है जिसमें वैश्विक वित्त और वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। पहले गैर-वित्तीय उत्तरदायित्व और सार्वजनिक प्रकटीकरण नीतियों की रफ़्तार काफ़ी धीमी थी, इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था लेकिन महामारी और लॉकडाउन ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हालांकि यह सब वे अपनी शर्तों पर ही कर रहे है। पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों (ईएसएस) के लिए की जा रही मांग को मानने के बजाय कंपनियां, वित्तीय संस्थानों और विनियामकों द्वारा अधिक लचीली और स्वैच्छिक पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।

पेरिस समझौता, सीओपी-2022, बहुपक्षीय विकास संस्थानों के लिए वित्तीय मध्यस्थ बनने वाले भारतीय वित्तीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि, कुछ बैंकों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का इक्विटी निवेश (अंतराष्ट्रीय वित्तीय निगमों (आईएफ़सी) का ग्रीन इक्विटी वेंचर के तहत फेडरल बैंक में 916 करोड़ रुपये का निवेश) - इन सभी कारकों ने भारतीय बैंकों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) ढांचे के तहत पर्यावरण और सामाजिक रक्षोपाय नीतियों को अपनाने के लिए वातावरण निर्मित किया है।

बैंकों द्वारा जवाबदेही लेने की शुरुआत से ही कई नीतियां आकांक्षात्मक प्रकृति की हैं। प्रभाव मूल्यांकन और शिकायत निवारण के अनिवार्य उपायों को लागू नहीं करती हैं। उल्लंघन के मामले में बैंकों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा परियोजनाओं को ऋण देने के पूर्व अथवा परियोजना के जीवन काल में ना तो किसी प्रकार की जवाबदेही नीति रखता है, ना ही किसी उत्तरदायी तंत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है जिसे बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली जवाबदेही नीति या प्रक्रियाओं के रूप में माना जा सकता है। बल्कि एसबीआई के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा था कि वे खराब ईएसजी स्कोर वाली कंपनियों को भी उधार देना जारी रखेंगे। हालांकि एचडीएफ़सी बैंक, नीति के मामले में बेहतर है। किसी भी असुविधा के लिए सुधार का वादा करता है लेकिन इसके भी दिशानिर्देश अधिकांशतः आकांक्षात्मक प्रकृति के हैं। जवाबदेही नीतियों के अनुपालन के मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका कोई उल्लेख बैंक की नीतियों में नहीं है। यहाँ भी उन लोगों तक पहुंचने का कोई तंत्र नहीं है, जो सीधे परियोजनाओं से प्रभावित होते है। फिर जब हम आईसीआईसीआई की ओर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके पास एक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रबंधन ढांचा तो है लेकिन एसईएमएफ़ में यह उल्लेख नहीं है कि नीति के अनुसार समस्या के निवारण के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा ना करने वाला, कौन और कैसे उत्तरदायी होगा। नीति के अनुसार निवारण को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी यहाँ तक की समस्या के समाधान की प्रक्रिया भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि बैंक स्वीकार करता है कि वह अभी अपनी नीतियों में इन चिंताओं को शामिल करने की प्रक्रिया में है। यहाँ स्पष्ट है कि बिना किसी जवाबदेही तंत्र के जवाबदेही नीतियों दंतहीन हैं। इसके अलावा, वित्तीय संस्थान परियोजना की मंजूरी के लिए मौजूदा कानूनों और नियमों पर भरोसा करते हैं। यह ईएसजी नीतियों में भी परिलक्षित होता है। भारत सरकार ने "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" रैंक को बढ़ाने की महत्वाकांक्षी दौड़ में 2022 तक 2000 कानूनों और विनियमों को "अप्रचलित" मानते हुए संशोधन करने का दावा किया है। 2020 की ईआईए अधिसूचना सरकार को "आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों" की घोषणा करने के लिए विवेकाधीन अधिकार देती है, जहां सार्वजनिक सुनवाई के बिना पर्यावरणीय मंजूरी दी जाएगी, यह किसी भी परियोजना को "रणनीतिक" भी मान सकती है जो ईआईए दायित्वों को समाप्त करती है। सार्वजनिक परामर्श के संबंध में समुदायों द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का समय 40 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस, क्लीयरेंस की वैधता के लिए वर्षों की संख्या बढ़ाना, बेसलाइन डेटा संग्रह पर मानदंडों में ढील देना आदि बदले हुए नियमों में अन्य समस्याएं हैं। इसी प्रकार प्रस्तावित श्रम कानून हड़तालों को गैरकानूनी तथा यूनियन बनाने की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाते है।

इस प्रकार देखा जाए तो ये किसी भी मजबूत सुरक्षा तंत्र के लिए कमजोर नींव गढ़ते हैं।

छवि 2: पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी के कारण भारत के मूल निवासियों को अपनी जीवन शैली के लिए खतरों का सामना करना पड़ता है। स्रोत: सर्वायवल

2. विभिन्न दृष्टिकोणों से रक्षोपाय नीति अपनाने की आवश्यकता

बड़े बुनियादी ढांचों और विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आबादी के विभिन्न तबकों और हितधारकों को अलग तरह से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, स्थानीय समुदाय के लिए तत्काल चिंता का विषय, स्थानीय पर्यावरण और आजीविका के विनाश से संबन्धित हो सकता है। एक कंपनी के निवेशकों के लिए चिंता बढ़ते जलवायु संकट की हो सकती है, जबकि बैंकरों के लिए प्रमुख मुद्दा ऐसे निवेशों की वित्तीय व्यवहार्यता होगी। इस प्रकार एक पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीति इन सभी मुद्दों पर ध्यान देती है। आइए इनमें से कुछ चिंताओं को थोड़ा और विस्तार से देखें।

2.1 जनपक्षीय दृष्टिकोण से जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता

तटीय समुदाय बहुप्रचारित सागर माला परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में वधावन बंदरगाह परियोजना के खिलाफ हजारों लोगों ने मार्च किया। महीनों से केरल में मछुआरा समुदायों ने अडानी पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद विझिंजम बंदरगाह परियोजना के पास डेरा डाला है। अदानी इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित परसा ईस्ट केटे बेसिन कोयला खदान परियोजना के लिए हसदेव में आदिवासी अपने वनों की भावना की रक्षा कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट के खिलाफ लड़ने के लिए दिनकिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके साथ क्रूरता की गई थी। ये सभी एक-दूसरे से बस कुछ ही महीने दूर हैं और फिर भी ये इन परियोजनाओं के प्रभावों से प्राकृतिक संसाधनों और आजीविका की रक्षा के लिए देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की भयावहता की तस्वीर नहीं देते हैं।

हमने देखा है कि जनसंघर्ष कई जगहों पर जनविरोधी परियोजनाओं को रोकने में सफल रहे हैं। वे उन्हें आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बनाने के लिए, समयावधि बढ़ाने में भी सक्षम रहे हैं। कुछ तो जीतने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट भी गए हैं। इन संघर्षों में से अधिकांश को उचित मुद्दों को उठाने के लिए गिरफ्तारियां, झूठे आरोप, हिंसक कार्रवाई और यहां तक कि मौत का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में, कंपनियां प्रतिरोध को आगे बढ़ाने और परियोजनाओं को स्थापित करने में सक्षम रही हैं।

ज्यादातर मामलों में जनता की चिंताओं को दूर नहीं किया जाता है क्योंकि इसके लिए कंपनी या वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए पर्याप्त ढांचा उपलब्ध नहीं है। वित्तीय संस्थानों के लिए जवाबदेही नीतियों और उत्तरदायित्व तंत्र का अस्तित्व, जनता के हाथों में एक और हथियार के रूप में कार्य कर सकता है जो हानिकारक परियोजनाओं से बचने और जवाबदेही नीतियों के उल्लंघनों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने में मदद करता है।

इसलिए, नीति को उन समुदायों से परामर्श करके विकसित करने की आवश्यकता है जो परियोजनाओं से प्रभावित होंगे। इसमें पूर्व-परियोजना मूल्यांकन, प्रभाव आकलन, स्वतंत्र और पूर्व सूचित सहमति, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास, समय-समय पर मूल्यांकन और निगरानी के लिए तंत्र, परियोजना के बाद की निगरानी और किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए जवाबदेही तंत्र से संबंधित खंड शामिल होने चाहिए। क्योंकि रास्ता बहुत स्पष्ट है, या तो मानवाधिकारों की रक्षा और जलवायु संकट को दूर करने का प्रयास करो, या या फिर व्यवसाय की सुविधा को बढ़ावा दो।

2.2 जनपक्षीय दृष्टिकोण से जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता

उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष से उभरे सामाजिक अनुबंध ने स्वतंत्र भारत की राजनीति और नीतिगत दिशा को निर्देशित किया। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जिसने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले उद्योगों और आर्थिक संस्थानों पर राज्य के नियंत्रण और संसाधनों के पुनर्वितरण की नींव रखी। विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) का गठन, योजना आयोग, श्रम कानूनों को लाना आदि इस समझ से बने हैं कि राज्य की जनता के प्रति भूमिका और जबाबदेही है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969) के उल्लेखित उद्देश्यों में, एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए बैंकिंग प्रणाली के त्वरित संचालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था। इसे सार्वजनिक विनियमन के अधीन लाते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले उपेक्षित और पिछड़े लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की अपनी परिभाषा में सार्वजनिक संस्थानों को शामिल किया गया है, जब मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) की जवाबदेही की बात आती है। यह बताता है:

38. 1 [(1)] राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रूप से सुरक्षित और संरक्षित सामाजिक व्यवस्था को बनाने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्र के सभी संस्थानों में सुनिश्चित हो सके।

2 [(2)] राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समुदायों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा।

39. राज्य का विशेष ध्यान इन दिशाओं में होना चाहिए -
(ए) कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हो।
(बी) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह वितरित किया जाए जिससे आम जनता की बेहतरी सुनिश्चित हो सके।
(सी) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधन कुछ लोगों तक सीमित ना हो।
(डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित हो सके।

46. राज्य जनता के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

1 [48ए. राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही को तय करते है। सार्वजनिक संस्थान निर्देशक सिद्धांतों से बंधे हुये हैं जो जनता के कल्याण विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों और देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का वादा करते हैं।

इस पुस्तिका में सार्वजनिक संस्थानों की परिभाषा केवल उन संस्थानों तक ही सीमित नहीं है जो सरकार के स्वामित्व में है बल्कि वे भी संस्थान इसमें शामिल हैं जो सार्वजनिक धन से संचालित होते हैं।

1990 के दशक से किए जा रहे ढांचागत सुधार, जिसके तहत व्यापार के पक्ष में मौजूदा कानूनों में संशोधन, कंपनी को परियोजनाओं के दौरान दी जाने वाली कॉर्पोरेट टैक्स छूट और अन्य सब्सिडी, जोखिम मुक्त व्यवसाय का मॉडल और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) शामिल है, सभी संस्थान जनता के बजाय पूंजी और कॉरपोरेट्स के पक्ष में काम कर रहे हैं। श्रम अधिकारों को कमजोर करने से लेकर तमाम मंजूरियों को "आसान" करने तक, इस तरह के कदमों ने एक तरफ मेहनतकश जनता के शोषण को बढ़ा दिया है और दूसरी ओर प्रकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूट को तीव्र किया है। बैंकों और एलआईसी सहित तमाम सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण का आत्मघाती अभियान संस्थानों की सार्वजनिक जवाबदेही को खत्म करने का एक और तरीका है।

सुरक्षा नीतियां यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सार्वजनिक धन से संचालित होने वाले सार्वजनिक संस्थानों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

2.3 वित्तीय संस्थानों के दृष्टिकोण से जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता

जोखिम के मामले में हमारा मानना है कि निवेश या लाभप्रदता के संदर्भ में "जोखिम" तथा सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में फिर से "जोखिम" के बीच अंतर है। हमें निवेश जोखिम को न्यूनतम करने के साथ-साथ प्रभाव जोखिम को न्यूनतम करने के लिए जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता है।

तथ्य यह है कि बैंकों द्वारा वित्त पोषित ऐसी विकास योजनाएँ जो गैर-वित्तीय (पर्यावरणीय और सामाजिक) प्रभावों के लिए जिम्मेदार है, सीधे तौर पर कानूनी और नैतिक रूप से बैंकों को उत्तरदायी बनाता है। यह धारणा अब वैश्विक स्तर पर स्थापित हो चुकी है। इस उत्तरदायित्व का अर्थ है कि बैंकों को उन हानिकारक परियोजनाओं का मूल्यांकन करना, हानिकारक प्रभावों को कम करना, क्षतिपूर्ति करना चाहिए जिनका वे वित्तपोषण करते हैं। वित्तीय जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि बैंक सतर्क निवेश का रास्ता अपनाएं।

यदि बैंक किसी ऐसी परियोजना में निवेश करते हैं जो पर्यावरण और स्थानीय समुदाय के लिए हानिकारक है एवं पर्यावरण के मौजूदा कानूनों और विनियमों के खिलाफ है, तो उनके निवेशों को कानूनी बाधाओं के कारण जटिलताओं से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि स्थानीय समुदाय से इसका विरोध होता है तो परियोजना ठप हो सकती है। तब इससे बैंकों को भारी नुकसान हो सकता है।

दोनों तरह के जोखिमों में कुछ ओवरलैप्स होते हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण अंतर है परिपेक्ष्य का है। पहला जोखिम वित्तीय लाभ के दृष्टिकोण से जोखिम के सवाल पर नजर डालता है, जबकि दूसरा प्रभाव को मुख्य मापदंड के रूप में रखता है, जिसके माध्यम से परियोजनाओं को निर्णय और जाँचा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई ऐसी परियोजना है जिसमें घरेलू कानूनों का उल्लंघन करते हुए संरक्षित वन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वित्तीय जोखिम परिप्रेक्ष्य ऐसी परियोजनाओं में निवेश के खिलाफ सलाह देगा। दूसरी ओर यदि वन क्षेत्र पर उच्च प्रतिकूल प्रभाव वाली कोई परियोजना है, लेकिन जिसमें कोई कानूनी उल्लंघन शामिल नहीं है, तो प्रभाव जोखिम दृष्टिकोण अभी भी इसमें निवेश करने के खिलाफ सलाह देगा। उदाहरण के लिए, हमारे विश्लेषण में, एचडीएफसी बैंक, अपने ऋण के लिए, उन कुछ भारतीय बैंकों में से एक है जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव का अनुपालन करते हैं और अपनी नीतियों में पर्यावरण सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) ढांचे को भी शामिल करते हैं। इसमें ऋण देने में पर्यावरण और सामाजिक जोखिम प्रबंधन पर एक खंड शामिल है। लेकिन यह अभी भी परिभाषित करने में विफल रहता है कि जोखिम से इसका क्या मतलब है। क्या यह केवल वित्तीय खतरे हैं जिसे सीमित अर्थ में देखा जाता है या फिर पर्यावरण और जनता को होने वाली हानी भी इसमें शामिल हैं।

2.3.1 बैंकों पर क्या भार पड़ता है।

जोखिमों को आगे चार व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है

ए) वित्तीय जोखिम

बैंकों के लिए निवेश और वित्तीय रिटर्न के संबंध में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वे जिन परियोजनाओं पर निवेश करते हैं उनसे हितधारकों को निश्चित रिटर्न मिलने की संभावना हो।

पर्यवेक्षण की कमी, संचालन में पारदर्शिता की कमी और बैंकिंग उद्योग में लोकतांत्रिक माहौल की कमी तथा कुछ अंधाधुंध उधारों ने आग में घी डालने का काम किया है जिसके चलते गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले पांच वर्षों में कुल एनपीए का कंपाउंडेड औसत वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) लगभग 30% है। रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में एनपीए की औसत वृद्धि लगभग 25% थी।

बी) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन

बैंक यह नहीं चाहते कि उनके निवेश देशी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों या परियोजना विकास कर्ताओं द्वारा दायित्वों के पालन के कारण जटिलताओं में फंस जाएं, इसलिए उनको जवाबदेही नीतियों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।

सी) पर्यावरणीय प्रभाव जोखिम, जलवायु न्याय, एसडीजी लक्ष्य और हरित निवेश

डी) यह सत्य है कि बैंकों के लिए, उदाहरण के लिए एसबीआई द्वारा जलवायु न्याय और संधारणीयता को केवल निवेश के अवसर के रूप में देखा जाता है। जबकि जबाबदेह बैंकिंग और सतत विकास के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। लेकिन यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि इन निवेशों से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह, आईसीआईसीआई बैंक के नीतिगत दस्तावेजों में जलवायु जोखिम और कार्बन संक्रमण का संदर्भ भी किसी ठोस कार्य योजना के बजाय वादों और बार-बार की प्रतिबद्धताओं तक सीमित है।

हालाँकि, दुनिया तेजी से जबाबदेह निवेश का मापदंड अपना रही है। हितधारकों की मांग है कि उनके निवेश से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव न हो। इस संबंध में बैंक को हितधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही और जलवायु संबंधी एसडीजी के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में इन जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करना होगा। जबकि यह कई तिमाहियों से बताया गया है कि इस तरह के निवेश का एक बड़ा हिस्सा केवल ग्रीनवाशिंग के लिए है। जलवायु संकट के इर्द-गिर्द चर्चा को देखते हुए, बैंकों को जवाबदेह ठहराने के लिए शायद अधिक कारणों और जागरूकता की आवश्यकता हैं।

ई) सामाजिक जोखिम:

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों के पास भी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार तंत्र नहीं है कि उनका ऋण कमजोर समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाल सके। लेकिन पर्यावरणीय जोखिमों के मामले में, इस बात की स्वीकार्यता बढ़ रही है कि विकास परियोजनाओं को कमजोर समुदायों के जीवन और आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए, और श्रम के लिए उचित रोजगार की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। ये कुछ एसडीजी का भी हिस्सा हैं जिनके लिए कुछ बैंक प्रतिबद्ध हैं। इन लक्ष्यों के वास्तविक पालन के संदर्भ में दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इनमें से प्रत्येक उत्तरदायित्व को लागू करने के लिए मानक हैं।

एफ) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम:

बढ़ती जागरूकता के कारण लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी संस्थाएँ उचित तरीके से व्यवहार करेंगी और यदि नहीं तो वे अपने व्यवसाय को कहीं और ले जाने को तैयार रहें। साथ ही कई संगठन एफआई को उनकी ईएसजी प्रतिबद्धताओं आदि पर ग्रेड और रेटिंग देते हैं, जो किसी विशेष संस्थान के साथ व्यापार करने के लोगों के निर्णयों को प्रभावित करता है।

जी) अंतर्राष्ट्रीय विकास:

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पेरिस समझौतों, सतत विकास लक्ष्यों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी) 2022 और आरबीआई नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स (NGFS) का हिस्सा बन गए है। इस दबाव के परिणामस्वरूप आरबीआई ने मॉनिटरिंग में जलवायु संबंधित जोखिमों को शामिल करने और वित्तीय संस्थाओं में जलवायु संबंधित जागरूकता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। निगरानी और वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु संबंधी जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा, यह नीति अभियान अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के प्रोत्साहन से आया है, जिसने कुछ भारतीय बैंकों में अपने हरित पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए निवेश किया है। हालांकि यह बैंकों के लिए जवाबदेही लेने की शुरुआत है, केवल रिपोर्टिंग और क्रेडिट मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पेरिस समझौतों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी) 2022 और आरबीआई जो फाइनेंशियल सिस्टम के हरे भरने के नेटवर्क (एनजीएफएस) के हिस्से बन गया है, इस दबाव के परिणामस्वरूप आरबीआई ने वित्तीय मॉनिटरिंग में जलवायु संबंधित जोखिमों को शामिल करने और वित्तीय संस्थाओं में जलवायु संबंधित जागरूकता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) से धक्के की ताकत से यह नीति चल रही है, जो कुछ भारतीय बैंकों में ग्रीन पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए निवेश किया है। हालांकि, बैंकों के लिए ज़िम्मेदारी लेने की शुरुआत होने के बाद, केवल रिपोर्टिंग और क्रेडिट अनुमान मानदंड तय करना पर्याप्त नहीं है।

3. भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन तंत्र

कोई केंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं होने के कारण, मुट्ठी भर बैंकों के अपने आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) दिशानिर्देश हैं। वे सभी पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को समझने और कम करने का लक्ष्य रखते हैं जो उनके उद्योग या कॉर्पोरेट ऋण पोर्टफोलियो से जुड़े होते हैं। इनमें से कुछ दिशानिर्देश परियोजना का मूल्यांकन करने के बाद तैयार किए जाने वाले एक ढांचे के बारे में बात करते हैं, जबकि कुछ बैंक प्रक्रिया और मौजूदा कानून, दिशानिर्देश और प्रदर्शन मानकों के अनुपालन का विस्तृत विवरण देते हैं। लेकिन यह नहीं परिभाषित करते हैं कि वे जोखिम और जोखिम मूल्यांकन से क्या समझते है। बहुत कम लोग शब्दावली, प्रभाव के श्रेणियां और आवश्यक प्रक्रियाओं की परिभाषा करते हैं।

ये नीतियां बहुत प्रारंभिक चरण में प्रतीत होती हैं, कुछ नियमों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता की कमी है। इसके अलावा, जिस जोखिम का वे उल्लेख करते हैं वह पर्यावरण और लोगों के लिए जोखिम के बजाय निवेश के लिए जोखिम है। इसके अलावा, कुछ बैंकों के पास 'बहिष्करण सूचियां' होती हैं जो उन संवेदनशील क्षेत्रों की गणना करती हैं जहां वे निवेश नहीं करते हैं जैसे कि वन्यजीव उत्पाद, रेडियोधर्मी सामग्री, ड्रिफ्ट नेट फिशिंग आदि। मानकीकरण के बिना, जिनके पास ऐसी सूचियां हैं, वे भी मनमाना हैं। उदाहरण के लिए एचडीएफसी की बहिष्करण सूची केवल उन परियोजनाओं तक सीमित है जो ओजोन क्षरण का कारण बनती हैं। ऐसे कई अन्य अत्यधिक प्रदूषणकारी या संभावित प्रदूषणकारी क्षेत्र हैं जो सूची में शामिल नहीं हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, नीतियां आकांक्षी और ओपन एंडेड हैं, उल्लंघन या शिकायतों के मामले में की जाने वाली ठोस कार्रवाई को परिभाषित नहीं करती हैं। बिना किसी जवाबदेही तंत्र के सुरक्षा नीतियां शायद ही कभी प्रभावी होती हैं। इसके अलावा, न तो वे समुदाय जिनके लिए नीतियां मदद करने का दावा करती हैं, न ही बैंकिंग समुदाय ऐसी नीतियों के अस्तित्व के बारे में गंभीर है। जबकि नीतियां और रिपोर्ट (हालांकि सीमित) सुलभ हैं, कोई भी बैंक कॉर्पोरेट कंपनियों को सार्वजनिक रूप से सुलभ पर्यावरण प्रभाव आकलन या विशेष ऋणों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान नहीं करता है। परियोजनाओं के जीवन काल में निगरानी प्रक्रिया और रिपोर्टिंग अभी भी अपारदर्शी है।

3.1 जवाबदेही नीतियाँ बनाने और लागू करने में नियामकों की भूमिका

2007 के बाद पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन पर बार बार ज़ोर देने के बावजूद, भारत के रिज़र्व बैंक ने कभी भी निर्भरता के मैकेनिज़्म को सुनिश्चित करने में बहुत कम योगदान दिया है। बावजूद हालांकि यह सत्य है कि राज्य जलवायु नियंत्रण और मानव जनसंख्या पर प्रभाव के बारे में कानूनों के माध्यम से मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है, लेकिन संबंधित डोमेन कवर करने वाले घरेलू कानूनों के अलावा वित्तीय संस्थानों पर विश्व स्तर पर विकसित विस्तृत संबंध को समझते हुए, मजबूत जवाबदेही नीति की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2022 में आयोजित 'जलवायु जोखिम और सतत वित्त' सर्वेक्षण ने दिखाया कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों को जलवायु संकट के वैश्विक संबोधन में उनकी ऋण पोर्टफोलियो को सहायक बनाने के लिए अधिक दूर तक जाना होगा। सर्वेक्षण बताता है कि शायद ही कोई बैंक अपने शीर्ष प्रबंधन के मूल्यांकन में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानदंड से संबंधित प्रदर्शन संकेतकों को शामिल करता है। ईएसजी से संबंधित पहलों और स्थायी वित्त को देखने के लिए अधिकांश बैंकों के पास अपने प्रशासनिक ढांचे में एक अलग वर्टिकल नहीं है, न ही वे अपने स्थायी वित्त पोर्टफोलियो के विस्तार या जलवायु जोखिम का जवाब देने की दिशा में एक स्पष्ट रणनीति पेश करने में सक्षम थे। आरबीआई के विनियमन विभाग के सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप (एसएफजी) द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 16 निजी वाणिज्यिक बैंकों, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और छह विदेशी बैंकों की भागीदारी देखी गई। सर्वेक्षण के आधार पर एसएफजी, बैंक के प्रशासनिक ढांचे में क्षमता निर्माण और जलवायु जोखिम मूल्यांकन को शामिल करने की सिफारिश करता है, और 'ग्रीन फाइनेंसिंग' के लिए उधार पोर्टफोलियो के बड़े हिस्से की वकालत करता है।

3.2 ग्राहक

बैंकों के लाखों ग्राहकों के लिए वित्तीय और नैतिक दोनों कारणों से जवाबदेही नीतियों वांछनीय हैं। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के बड़े बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश ने भारतीय लोगों की बचत और व्यक्तिगत निवेश को वित्तीय जोखिम के साथ-साथ बचत खाता वाले लगभग हर आम व्यक्ति को उन परियोजनाओं के लिए पार्टी बना दिया है जो क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ावा देता है, लोगों को बेघर करता है और आजीविकाओं को नष्ट करता है। वित्तीय जोखिम के स्पष्ट कारण से परे, ग्राहकों को यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा बैंकों द्वारा कहाँ निवेश किया जा रहा है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन एक सामान्य चिंता का विषय बनता जा रहा है, वैसे-वैसे बैंकों को सार्वजनिक प्रकटीकरण नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, जहाँ ग्राहकों को उनके बैंकों के निवेश विकल्पों के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जा सके। और प्रकटीकरण तंत्र को और मजबूत करने के लिए, ताकि वे केवल रिपोर्टिंग न रहें, जवाबदेही नीति किए जाने की आवश्यकता है।

3.3 हितधारक प्रभाव

विकास परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रभाव से संबंधित जोखिमों और ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने वाले वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही की स्वीकार्यता और मान्यता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभाव, और कमजोर आबादी पर प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की बढ़ी हुई जागरूकता और सक्रियता का मतलब है कि बैंकों को अपनी नीतियों, ऋण देने और उन परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन के बारे में अधिक पारदर्शी होना चाहिए, जिनके लिए वे निधि देते हैं। हितधारक नहीं चाहते हैं कि उनका पैसा उन परियोजनाओं में निवेश किया जाए जो स्पष्ट जलवायु और सामाजिक जोखिम पैदा करते हैं। वे वास्तविक अर्थों में हरित वित्तपोषण चाहते हैं।

समयबद्ध तरीके से उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, यह आवश्यक है कि आरबीआई और सेबी जैसे नियामक निकाय जवाबदेही नीतियों और उनके अनुपालन में ध्यान दें।

फोटो सौजन्य: Pexels से योगेन्द्र सिंह

निष्कर्ष

जवाबदेही की पुनर्कल्पना: आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) तंत्र से जवाबदेही नीति तक

एक जवाबदेही नीति के बजाय भारतीय बैंकिंग संस्थान एक पर्यावरण सामाजिक और शासन (ईएसजी) ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं जिसका दायरा सीमित है। एक ईएसजी ढांचा एक रिपोर्टिंग प्रणाली है जो कार्बन उत्सर्जन जैसे प्रभाव और निवेश जोखिम को मापने का प्रयास करता है। सतत विकास में निवेश को प्रोत्साहित करता है और उधारकर्ताओं एवं बैंकों द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। पेरिस समझौतों, सतत विकास लक्ष्यों, पार्टियों के सम्मेलन (COP) 2022 और RBI के नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स (NGFS) का हिस्सा बनने के दबाव के परिणामस्वरूप, RBI ने वित्तीय निगरानी में जलवायु संबंधी जोखिमों को प्राथमिकता दी है और साथ ही वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु संबंधी जागरूकता पैदा पैदा करने पर ज़ोर दिया है। इसके अलावा यह नीति अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमों (IFC) के दबाब के कारण भी आई है जिसने कुछ भारतीय बैंकों में अपने हरित पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए निवेश किया है। हालांकि यह बैंकों के लिए जवाबदेही लेने की शुरूआत है जिसमें रिपोर्टिंग और क्रेडिट मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है।

कोई केंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं होने के कारण, मुट्ठी भर बैंकों के अपने आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक दिशानिर्देश हैं। वे सभी बड़े पैमाने पर या कॉर्पोरेट ऋणों के लिए अपने उधार पोर्टफोलियो के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को समझने और कम करने का लक्ष्य रखते हैं। इनमें से कुछ दिशानिर्देश एक ऐसे ढांचे के बारे में बात करते हैं जो परियोजना के मूल्यांकन के बाद तैयार किया जाएगा (जैसे एचडीएफसी बैंक), जबकि कुछ प्रक्रिया और मौजूदा कानूनों, दिशानिर्देशों और प्रदर्शन मानकों का विवरण देते हैं जिनका बैंक पालन करेगा जैसे एक्सिस बैंक)। हालांकि जोखिम और जोखिम मूल्यांकन को परिभाषित किए बिना इस सब का क्या मतलब है। बहुत कम बैंक (फेडरल बैंक की तरह) शब्दावलियों, प्रभावों की श्रेणियों और आवश्यक प्रक्रिया को ठीक से परिभाषित करते हैं।

ये नीतियां बहुत प्रारंभिक चरण में प्रतीत होती हैं, कई नियमों और प्रक्रियाओं में स्पष्टता की कमी है। इसके अलावा, जिस जोखिम का वे उल्लेख करते हैं वह पर्यावरण और लोगों के लिए जोखिम के बजाय निवेश के लिए जोखिम है। कुछ बैंकों के पास 'बहिष्करण सूची' होती है जो उन संवेदनशील क्षेत्रों की गणना करती है जहां वे निवेश नहीं करते हैं जैसे कि वन्यजीव उत्पाद, रेडियोधर्मी सामग्री, ड्रिफ्ट नेट फिशिंग आदि।

सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संदर्भ में ऐसी जवाबदेही नीतियाँ की जरूरत है जो उन समुदायों के साथ परामर्श करके बनाई जाए जो परियोजनाओं से प्रभावित हुए हैं या प्रभावित होने की संभावना है। जवाबदेही नीति की मांग का किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि यह विकास के उस मॉडल की स्वीकृति है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि यह लोगों के हाथों में वित्तीय संस्थानों और जीवन को नष्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ लड़ने का एक और साधन मात्र है।

जोखिम प्रबंधन और जवाबदेही ढांचा कैसा दिखना चाहिए

जैसा कि दुनिया खुद को एक बढ़ते जलवायु संकट के बीच पाती है, दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों को नीतिगत ढांचे की ओर बढ़ना होगा जो उन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति संवेदनशील हैं जिन्हें वे वित्त पोषित करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव जोखिम को प्राथमिकता देने का अतिरिक्त लाभ वित्तीय जोखिमों कम करने में मदद करता है। यहां हम पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीति पर अपेक्षाओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं। यह सूची बैंकों की कुछ मौजूदा आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमों के प्रदर्शन मानकों और समुदायों की कुछ लंबे समय से लंबित मांगों का अध्ययन करके बनाई गई है।

- **अनिवार्य प्रभाव आकलन मानदंड:** सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईएसएस नीति अनिवार्य होनी चाहिए। नीतियों के इस क्रियात्मक पहलू के बिना, यह दंतहीन हो जाता है और अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। यह संस्थानों द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाओं पर लागू होना चाहिए। जवाबदेही नीतियों के लिए पूर्व-अनुमोदन और अनुमोदन के बाद के चरण में अनिवार्य आवधिक प्रभाव मूल्यांकन प्रावधान होना चाहिए। इन प्रावधानों में परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत तंत्र के अलावा बैंक या सक्षम तीसरे पक्ष द्वारा जांच का एक घटक शामिल होना चाहिए।

- **अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं और तकनीकी आवश्यकताएं:** जवाबदेही नीतियों में विस्तृत प्रभाव, आँकड़ों और तकनीकी आवश्यकताओं को समाविष्ट करना आवश्यक है, सामान्य रूप से और विशिष्ट सामाजिक और पर्यावरण सम्बंधी मुद्दों के लिए भी इन नीतियों में विशिष्ट सामाजिक और पर्यावरण सम्बंधी चिंताओं के अनुकूल बनाने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को विवेचना के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए।

- **स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र (आईएएम) :** एक स्वतंत्र तंत्र होना चाहिए जो लोगों के लिए शिकायत दर्ज कराने, ईएसएस के उल्लंघन की जांच की मांग करने के लिए उपलब्ध हो। स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र के पास ऐसे निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए जो बैंक प्रबंधन से स्वतंत्र हों।

- **प्रभाव परिप्रेक्ष्य:** पर्यावरण और लोगों पर बड़े पैमाने की परियोजनाओं के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ नीति को अक्षरश: सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह नीति में बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए।

- **अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श और पूर्व सूचित सहमति:** किसी भी विकास परियोजना को लागू तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक संभवतः प्रभावित समुदायों से अनिवार्य परामर्श और सहमति प्राप्त न हो। प्रभावित समुदायों को संभवतः सबसे अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

- **पारदर्शिता:** चूंकि विकास परियोजनाओं में लोगों का धन शामिल होता है और बड़ी आबादी को प्रभावित करता है, इसलिए वित्तीय संस्थानों को उपरोक्त सभी के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता बरतने की आवश्यकता है। ये सभी तत्व: वित्त, मूल्यांकन मानदंड और नीति, अनुबंध समझौता आदि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

- **शिकायत निवारण तंत्र:** वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजनाओं से प्रभावित सभी लोगों के लिए सुलभ, तत्काल और प्रतिक्रियाशील जीआरएम स्थापित करने की आवश्यकता है।

नीति को निम्नलिखित तीन चरणों में होना चाहिए: पूर्व उधार, परियोजना का जीवन चक्र और जवाबदेही और पारदर्शिता।

क. उधार देने से पहले के चरण में उन सभी प्रक्रियाओं और उचित कार्यों को शामिल किया गया है जो किसी परियोजना के लिए ऋण देने से पहले वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों के लिए आवश्यक हैं।

- बहिष्करण सूची के लिए जाँच करें
- आवश्यक अनुपालन की जाँच करें
- सूचना प्रकटीकरण (ईआईए, एसआईए और पुनर्वास/पुनर्वास और अन्य योजनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए)
- स्वतंत्र और पूर्व सूचित सहमति:
- सूचना प्रकटीकरण के लिए नियत समय के साथ सार्वजनिक परामर्श
- पिछले डिफ़ॉल्ट के लिए जाँच करें

ख. परियोजना का जीवन चक्र:

- पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के आधार पर परियोजना का वर्गीकरण
- निगरानी तंत्र श्रेणियों के आधार पर

- **पर्यावरण और सामाजिक श्रेणियों के गठन की स्पष्ट परिभाषा-**
  - मजदूर और काम करने की स्थिति
  - संसाधन दक्षता और प्रदूषण निवारण
  - सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षण
  - भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास
  - जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन
  - आदिवासी, अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय
  - सांस्कृतिक विरासत
  - वित्तीय मध्यस्थ
  - हितधारक के साथ संबंध और सूचना प्रकटीकरण

ग. जवाबदेही और पारदर्शिता:

- उधार/निवेश का सार्वजनिक प्रकटीकरण:
- अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में वेबसाइट इत्यादि में आर्थिक सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) नीतियों का प्रकटीकरण।
- समुदायों के पास शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी परियोजना और वित्तपोषक दोनों स्तरों पर उपलब्ध हो।
- निगरानी प्रक्रियाओं की रिपोर्टिंग और हर तिमाही में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

ग्रंथ सूची

- The Times of India. 2022. “384 Infra Projects Show Cost Overruns of Rs 4.52 Lakh Cr,” October 23, 2022.12. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/384-infra-projects-show- cost-overruns-of-rs-4-52-lakh-cr/articleshow/95043347.cms.
- “Developing Distress.” n.d. Accessed November 29, 2022. https://www.downtoearth.org.in/indepth/developing-distress-27724.
- Displacement and Rehabilitation, URL: http://164.100.47.193/Refinput/New_Reference_Notes/English/DisplacementandRehabilitation.pdf
- Rao, M Rajeshwar. n.d. “Exploring How Climate Scenario Exercises Can Be Used to Identifr Vulnerabilities in RBI Supervised Entities’ Balance Sheets, Business Models and Gaps in Their Capabilities for Measuring and Managing Climate-Related Financial Risks;,” 1.
- Eckstein, David, Vera Künzel, Laura Schäfer, and Maik Winges. n.d. “Global Climate Risk Index 2020 | Germanwatch e.V.” Accessed November 29, 2022. https://www.germanwatch.org/en/17307.
- “IFC Equity Investment in Federal Bank to Promote Green Recovery, Improve Access to Finance for Smaller Businesses.” n.d. IFC. Accessed November 29, 2022. https://ifcpressreleasesprod.aseprod.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26537.
- “Reserve Bank of India - Reports.” n.d. Accessed November 29, 2022. https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1215.
- “SBI Does Balancing Act between Financing Coal Projects, Appeasing Investors | Business Standard News.” n.d. Accessed November 29, 2022. https://www.business-standard.com/article/companies/biggest-bank-in-india-torn-between-blackrock-and-financing-coal-projects-121060300157_1.html.
- “SBI Has Invested My Money in a Firm That Makes Cluster Bombs.” 2016. Centre for Financial Accountability (blog). August 23, 2016. https://www.cenfa.org/sbi-has-invested-my-money-in-a-firm-that-makes-cluster-bombs/.
- The Economic Times. 2016. “SBI in ‘Hall of Shame’ of Banks Funding Cluster Bomb Makers,” June 20, 2016. https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/sbi-in-hall-of-shame-of-banks-funding-cluster-bomb-makers/articleshow/52819714.cms.
- Bhalla, Nita. 2016. “SBI Says No Law Broken in Funding Cluster Bomb Maker.” Mint. June 23, 2016. https://www.livemint.com/Industry/U8A5L3aT5iGnAhHxUPt500/State-Bank-of-India-says-no-law-broken-in-funding-cluster-bo.html.
- Team, O. C. I. 2021. “Unused Tools: How Central Banks Are Fueling the Climate Crisis.” Oil Change International (blog). August 24, 2021. https://priceofoil.org/2021/08/24/unused-tools-central-banks/.
- https://www.downtoearth.org.in/indepth/developing-distress-27724
- https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/adivasis-dams-and-displacement-india
- https://tribal.nic.in/writereaddata/AnnualReport/AnnualReport2016-17.pdf
- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) (2007) India: Large Numbers of IDPs are Unassisted and in Need of Protection: A Profile of the Internal Displacement Situation, www.internal-displacement.org, date accessed on 22 October 2010.
- https://core.ac.uk/download/pdf/15986769.pdf Development Projects vs. Internally Displaced Populations in India: A Literature Based Appraisal

- http://blueeconomytribunal.org/wp-content/uploads/EAST%20&%20WEST%20COAST%20INDIA-2-compressed.pdf
- https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/many-shades-of-a-blue-economy-sagarmala-project/article20104312.ece
- https://www.thehindubusinessline.com/blink/cover/coastline-erosion-in-keralas-capital/article30818347.ece
- https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NGFS03112021_EN.pdf
- "5 Years of IBC: Acquirers Laugh Their Way to Banks, Haircuts Bleed Lenders - BusinessToday." n.d. Accessed December 12, 2022. https://www.businesstoday.in/opinion/columns/story/5-years-of-ibc-acquirers-laugh-their-way-to-banks-haircuts-bleed-lenders-302629-2021-07-28.
- "Report of the Committee for Inspection of M/s Adani Port & SEZ Ltd. Mundra, Gujarat (Sunita Narain Committee on Adani) - India Environment Portal | News, Reports, Documents, Blogs, Data, Analysis on Environment & Development | India, South Asia." n.d. Accessed December 12, 2022. http://www.indiaenvironmentportal.org.in/content/374099/report-of-the-committee-for-inspection-of-ms-adani-port-sez-ltd-mundra-gujarat-sunita-narain-committee-on-adani/.
- "Reserve Bank of India - RBI Bulletin." n.d. Accessed December 14, 2022. https://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20022.

वित्तीय जवाबदेही केंद्र (CFA) वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को आगे बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन करता है। वित्तीय संस्थानों, खासकर बैंकों, की पूंजी का स्रोत जनता का पैसा ही है। इसीलिए वित्तीय संस्थानों को जनता और समाज की ओर जवाबदेह होना जरूरी है। हम इस प्रक्रिया में आंदोलनों, संगठनों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और युवाओं की मदद करने के लिए अनुसंधान, अभियान और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और हम उन अभियानों में भाग लेते हैं जो बैंकिंग और अर्थव्यवस्था मे प्रगतिशील बदलाव ला सकते हैं।

हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के निवेश की निगरानी करने का प्रयास करते हैं, और उन नीतियों पर काम करते हैं जो देश के बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। हमारी कार्यशालाएं और अल्पकालिक पाठ्यक्रम वित्त की दुनिया को उजागर करती हैं और नागरिकों को बैंकों और सरकार को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद करती हैं।

CFA
Centre for Financial Accountability